

(ङ) जी, हां। ऐसा इसलिये है कि इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में किया जाने वाला कार्य अधिकांशतः वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्वरूप का है। किंतु पिछले कुछ वर्षों में हिन्दी के कुछ लब्धप्रतिष्ठ तथा मूर्धन्य साहित्यकारों की अनेक कृतियां खरीदी गई हैं तथा वे इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। हाल ही में बड़ी संख्या में हिन्दी पत्र पत्रिकाएँ भी मंगवाई जाने लगी हैं।

(च) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये ठोस उपाय किये जा रहे हैं साथ ही न केवल इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अहिन्दी भाषा भाषी अधिकारियों कर्मचारियों को हिन्दी में प्रशिक्षण दिया जाता है, अपितु आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को भी हिन्दी अशुलिपि टाइपिंग में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से उन्हें बारी-बारी से गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रायोजित किया जाता है।

पर्यावरण विभाग में राजभाषा का प्रयोग

1027. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन समय पर न किये जाने वर्ष में चार बार उसकी बैठक न बुलाये जाने और ऐसी बैठकों में लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) हिन्दी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को स्थायी आधार पर नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित न किये जाने

के संबंध में किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि वेतन तथा पदोन्नति के अवसर कम होने के परिणामस्वरूप अनुवादकों के उपलब्ध न होने की वजह से हिन्दी साहित्य के प्रकाशनों का कार्य तथा अनुवाद कार्य पिछड़ गया है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि विभागीय पुस्तकालय में हिन्दी प्रकाशनों की संख्या अंग्रेजी प्रकाशनों से कम है; और

(च) हिन्दी के विकास, उत्तरोत्तर प्रयोग तथा प्रचार-प्रसार के लिये और हिन्दी में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गये हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पर्यावरण विभाग 1-11-1980 से स्थापित किया गया था। पर्यावरण विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति मार्च, 1983 में गठित की गई है तथा इसकी पहली बैठक 14-4-1983 को सम्पन्न हुई है, समिति के गठन के देरी का कारण यह है कि विभाग अपने रचनात्मक स्तर पर था तथा आवश्यक कर्मचारी भी नहीं थे।

(ख) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रिय सचिवालय राजभाषा सेवा बनाई जा रही है। सेवा बनाये जाने तक हिन्दी अधिकारी एवं हिन्दी कर्मचारियों के पद तदर्थ आधार पर भरे जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्यों कि विभाग राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक अप्रैल, 1983 में हुई और उसमें किये गये निर्णयों पर कार्यवाही को जा रही है।

(घ) विभाग में अनुवाद का कार्य अद्यतन है। अनुवादकों के वेतन ढाँचे तथा उनकी पदोन्नति के पर्याप्त मार्ग का सम्बन्ध राजभाषा विभाग से है।

(ङ) पर्यावरण विभाग एक वैज्ञानिक विभाग है तथा हिन्दी की पुस्तकें अंग्रेजी की पुस्तकों से कम हैं। फिर भी हिन्दी की अधिकाधिक पुस्तकें पुस्तकालय में लाई जा रही हैं।

(च) राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन से आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति से हिन्दी के विकास, प्रगामी, प्रयोग और प्रचार तथा हिन्दी में प्रशिक्षण देने के लिये कदम उठाए जायेंगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राजभाषा का प्रयोग

1028. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन समय पर न किये जाने, वर्ष में चार बार उसकी बैठक न बुलाये जाने और ऐसी बैठकों में लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) हिन्दी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को स्थायी आधार पर नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों को क्रियान्वित न किये

जाने के संबंध में किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि वेतन तथा पदोन्नति के अवसर कम होने के परिणामस्वरूप अनुवादकों के उपलब्ध न होने की वजह से हिन्दी साहित्य के प्रकाशनों का कार्य तथा अनुवाद कार्य पिछड़ गया है ;

(ङ) क्या यह भी सच है कि विभागीय पुस्तकालय में हिन्दी प्रकाशनों की संख्या अंग्रेजी प्रकाशनों से कम है ; और

(च) हिन्दी के विकास, उत्तरोत्तर प्रयोग तथा प्रचार-प्रसार के लिये और हिन्दी में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी तथा महानगर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वो० पटिल) : (क) दिसम्बर, 1982 में इस विभाग के लिये एक हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समिति को यथा शीघ्र बैठक बुलाने के लिए विभाग आवश्यक कदम उठा रहा है।

(ख) यहां हिन्दी अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के लिये पद है और उन्हें नियमित आधार पर भरा गया है।

(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सिफारिशों को सामान्यतः क्रियान्वित किया जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी, हां। पुस्तकालय में विभाग